न्यायिक उत्तरदायित्व पर उप–समिति

बनाम

भारत का संघ और अन्य

8 मई, 1991

[बी. सी. रे, एल. एम. शर्मा, एम. एन. वेंकटचलिया,

जे. एस. वर्मा और एस. सी. अग्रवाल, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1950/न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968: अनुच्छेद 124 (5)–एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जांच

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आचरण से संबंधित उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई–संसद सदस्यों द्वारा नोटिस स्वीकार करने और एक जांच समिति का गठन करने में लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाई।

वैधता और कार्यान्वयन–मुख्य मामले की शीघ्र सुनवाई का निर्देश देने वाले अंतर्वर्ती राहत न्यायालय के लिए आवेदन। याचिकाकर्ता–समिति, अधिवक्ताओं के एक निकाय द्वारा दायर एक रिट याचिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके आचरण से संबंधित दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के संबंध में केंद्र सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है, ने भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 124 (5) के तहत संसद सदस्यों द्वारा पेश प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार करने में लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाई की वैधता और कार्यान्वयन के बारे में कुछ सवाल उठाए हैं।

कुछ हस्तक्षेप आवेदन, रिट याचिका का विरोध करते हुए, और कुछ अन्य रिट याचिकाएं कमोबेश सरकार का समर्थन करती हैं। यह सवाल उठाते हुए कि क्या विचाराधीन प्रस्ताव लोकसभा के विघटन से बच गया या नहीं, भी दायर किया गया था।

अंतरिम निर्देश के लिए प्रार्थना करते हुए, जो मुख्य रिट याचिका में प्रार्थना के समान था, याचिकाकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया था

समिति ने कहा कि संस्थान और शीर्ष न्यायालय के रूप में इसकी प्रतिष्ठा में जनता का विश्वास बनाए रखने की सख्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक था कि संबंधित न्यायाधीश जांच के लंबित रहने के दौरान न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने से दूर रहें, और तदनुसार एक निर्देश जारी किया जाए, या रिट याचिका का निपटारा होने तक, केंद्र सरकार को सभी आवश्यक खर्च उठाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। सुचारू और कुशल कार्यप्रणाली के लिए समिति को सुविधाएँ। रिट याचिका और संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई का निर्देश देते हुए, यह न्यायालय,

अभिनिर्धारित: 1.1 प्रकृति और महत्व को ध्यान में रखते हुए

संबंधित मुद्दों पर, यह उचित है कि संबंधित रिट याचिकाओं के साथ मुख्य मामले की सुनवाई जितनी जल्दी हो सके की जाए। वास्तव में, इस मामले को 9 जुलाई, 1991 को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और मामलों की सुनवाई समापन तक दिन–प्रतिदिन चलती रही। [744 डी}

1.2 इन परिस्थितियों में, एक पर शुरू करना उचित नहीं है अंतर्वर्ती राहत के लिए प्रार्थना की जांच। हालाँकि, इस स्तर पर किसी भी अंतर्वर्ती आदेश को जारी करने के लिए न्यायालय की अनिच्छा को किसी भी तरह से मुद्दों के गुण–दोष पर राय की अभिव्यक्ति और समिति के कामकाज में बाधा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, यदि समिति अन्यथा मामले को आगे बढ़ाने के लिए उचित समझती है। [744 ई–एफ]

मूल अधिकारिता: 1991 की रिट याचिका संख्या 491।

में

आई. ए. सं. 1/ 1991

के साथ

रिट याचिका सं 541 & 560 1991 आदि।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)।

जी. रामास्वामी, महान्यायवादी, शांति भूषण, अशोक

देसाई, हरदेव सिंह, सुश्री इंदिरा जयसिंह, पी. एस. पोती, राजिंदर सच्चर, एम. के. राममूर्ति, आर. के. गर्ग, एस. के. ढोलकिया, संतोष हेगड़े, वी. एन. गणपुले, तपस रे, एन. बी. शेट्टी, पी. पी. राव, कपिल सिब्बल, डी. एस. तेवतिया, हरि स्वरूप, जयंत भूषण, प्रशांत भूषण, सुश्री मधु मूलचंदानी, सुश्री कामिनी जैसवाल, ए. के. श्रीवास्तव, ई. एम. एस. अनम, एन. डी. गर्ग, ए. एम. खानविलकर और सुश्री ए. सुभाषिनी।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

यह रिट याचिका "सब–कॉम" शैली के अधिवक्ताओं के एक निकाय द्वारा दायर की गई है।

न्यायिक जवाबदेही पर समिति "और 108 सदस्यों द्वारा पेश प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार करते हुए लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाई की वैधता और कार्यान्वयन के बारे में कुछ सवाल उठाती है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के साथ पठित अनुच्छेद 124 (5) के तहत संसद और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के एक न्यायाधीश से मिलकर एक जांच समिति का गठन करना।

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायविद के खिलाफ किए गए कदाचार के आरोपों की जांच करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके आचरण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

रिट याचिका में मुख्य प्रार्थना यह है कि संघ सरकार

जाँच समिति को अपने संवैधानिक और वैधानिक कार्यों को करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया जाए; और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को समिति के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संबंधित न्यायाधीश को कोई भी न्यायिक कार्य आवंटित करने से बचने का निर्देश दिया जाए। बाद के अनुरोध के संबंध में कि नोटिस भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास जाना चाहिए, हम सोचते हैं कि मामले के पहलू को वर्तमान के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए और अंतिम सुनवाई के उचित चरण में विचार किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को दिए गए निर्देशों के संबंध में, केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा दिए गए एक हलफनामे के माध्यम से अपना रुख स्पष्ट किया है कि उसके विचार में संसद के 108 सदस्यों द्वारा शुरू किया गया प्रस्ताव, जिस पर अध्यक्ष ने निर्णय लिया था –

एक समिति का गठन किया जो लोक सभा के विघटन के साथ समाप्त हो गई थी

सभा और यह कि इस मामले में आगे कुछ नहीं किया जाना है। इस दृष्टिकोण से, जैसा कि हलफनामे में कहा गया है, भारत सरकार ने राष्ट्रपति को कोई अधिसूचना जारी करने की सलाह नहीं दी, जैसा कि आवश्यक है।

संविधान की दूसरी अनुसूची के पैरा 11 (बी) (आई), भाग डी के साथ पठित पैरा 9 इस न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को सक्षम बनाता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनके द्वारा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने में बिताए गए समय को उनकी 'वास्तविक सेवा' के हिस्से के रूप में गिनेंगे। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कार्य करने वाले न्यायाधीशों के संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए

समिति, इस तरह के कार्य के निष्पादन में उनके द्वारा बिताए गए समय को न्यायाधीशों के रूप में उनकी 'वास्तविक सेवा' के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा संबंधित प्रावधानों के तहत कोई अधिसूचना आवश्यक नहीं है।

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कुछ हस्तक्षेपकर्ता जो

रिट याचिका का विरोध करने के लिए, रिट याचिका के खिलाफ अपने रुख के अलावा, अपनी खुद की अलग–अलग रिट याचिकाएं भी दायर की हैं, जिसमें वे कमोबेश सरकार द्वारा उठाए गए रुख का समर्थन करना चाहते हैं, यह सवाल उठाते हुए कि क्या प्रस्ताव लोकसभा के विघटन से बचता है या नहीं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री शांति भूषण ने कहा कि

आग्रहपूर्ण याचिका में कहा गया है कि शीर्ष संस्थान और इसकी प्रतिष्ठा में जनता का विश्वास बनाए रखने की सख्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि संबंधित न्यायाधीश को अपने खिलाफ जांच के लंबित रहने के दौरान न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने से बचना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उस प्रभाव का निर्देश जारी नहीं किया जाता है, तो कम से कम यह आवश्यक रूप से निर्देश दिया जाना चाहिए कि गुण–दोष के आधार पर रिट याचिका का निपटारा होने तक, भारत संघ समिति को ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो इसके प्रभावी और त्वरित कामकाज के लिए आवश्यक हों। श्री शांति भूषण ने कहा कि भले ही रिट याचिका अंतिम रूप से विफल हो जाए, किसी को कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंचेगी और इसका परिणाम केवल यह होगा कि न्यायाधीशों के प्रतिष्ठित निकाय को आरोपों की जांच करने का अवसर मिलेगा

एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ और यदि वे आरोपों को निराधार पाते हैं, तो संबंधित न्यायाधीश को उसके आचरण के खिलाफ आरोपों और संदेह से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने आग्रह किया कि यदि इस तरह का निर्देश या अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाता है तो यह देश में शीर्ष न्यायालय के रूप में न्यायालय की छवि को गंभीर रूप से खराब करेगा और इसके द्वारा दिए गए न्याय की गुणवत्ता में लोगों के विश्वास को प्रभावित करेगा।

हमने इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की है और

इसमें शामिल मुद्दों की प्रकृति और महत्व को ध्यान में रखते हुए यह उचित है कि संबंधित रिट याचिका के साथ मुख्य मामला यह बताता है कि सभी पक्षों की दलीलें दस कार्य दिवसों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए और सभी पक्षों के लिए विद्वान वकील और हस्तक्षेप करने वालों को 1 जुलाई, 1991 तक अपनी लिखित दलीलें अग्रिम रूप से दायर करनी चाहिए। प्रत्येक वकील के लिए वास्तविक सुनवाई का समय होगा 9 जुलाई, 1991 को सुनवाई की शुरुआत में विभाजित किया गया। में।

इस मामले के इस दृष्टिकोण के लिए, हम उचित समझते हैं कि इसके समर्थन में विवाद और प्रार्थना की जांच शुरू न की जाए

अंतर्वर्ती राहत।

हम, हालांकि, यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी जारी करने के लिए हमारी अनिच्छा

इस स्तर पर अंतर्वर्ती आदेशों को एक्सप्रे के रूप में नहीं माना जाएगा। मुद्दों के गुणों पर किसी भी तरह से राय देना और यह भी नहीं होगा समिति के कार्यकरण में बाधा के रूप में समझा जाएगा यदि समिति अन्यथा इसके साथ आगे बढ़ना उचित समझती है बात है।

हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन मामलों के लंबित रहने के दौरान

इस न्यायालय के समक्ष इसके बाद किसी अन्य मामले में कोई कार्यवाही लंबित या दायर नहीं की गई है।

अदालत को सुना जाएगा या मुद्दों से संबंधित कोई आदेश पारित किया जाएगा।

इन मामलों में शामिल।

याचिका का निपटारा।